बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 137 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 13 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली में कोई भी लड़की ग्रेजुएशन तक की शिक्षा से वंचित नहीं रहनी चाहिए - सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली की सभी लड़कियों को कम से कम स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को अवसर प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है। गुप्ता ने अपनी सरकार द्वारा शुरू की गई लखपति बिटिया योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र लड़की को स्नातक करने के बाद 1.25 लाख रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, मेरी कामना है कि दिल्ली में कोई भी लड़की स्नातक स्तर तक की शिक्षा से वंचित नहीं रहे।

अविश्वास प्रस्ताव पर ओम बिरला- लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी, नेता प्रतिपक्ष को कभी नहीं रोका; नियम सबसे ऊपर

नई दिल्ली ।

लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आज पहली बार आसन पर आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है और नेता प्रतिपक्ष को कभी नहीं रोका गया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद के नियम सर्वोपरि हैं और कोई भी व्यक्ति नियम से ऊपर नहीं है, चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों न हों। ओम बिरला ने बताया कि सदन में पिछले दो दिनों में 12 घंटे से अधिक बहस हुई, ताकि सभी सदस्यों के विचार और चिंताएं सामने आ सकें। उन्होंने कहा -यह सदन 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यहां हर सांसद अपनी जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं के साथ आता है। मैंने हमेशा कोशिश की कि हर सांसद नियमों के तहत अपनी बात रखे। मैं हर उस सांसद को बोलने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता रहा जो कम बोलते थे, क्योंकि बोलने से लोकतंत्र का संकल्प मजबूत होता है।-

हर सदस्य का आभारी हूं- ओम बिरला

उन्होंने सदन को विचारों का जीवंत मंच बताते हुए कहा कि पिछले दो दिन में सभी सदस्यों की बातों को गंभीरता से सुना गया। हर सदस्य का आभारी हूं, चाहे वे आलोचक ही क्यों न रहे हों। यही विशेषता है कि यहां हर आवाज सुनी जाती है। यह आसन किसी व्यक्ति का नहीं है, यह लोकतंत्र की महान भावना का प्रतिनिधि है।

नियमों के तहत बोलने का अधिकार

ओम बिरला ने विपक्ष की शिकायतों का भी जवाब दिया। कुछ सदस्यों का

कहना था कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका जाता है। इस पर उन्होंने कहा मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी हो, उसे सदन में नियमों के तहत बोलने का अधिकार है। कुछ लोगों का मानना था कि सदन के नेता हर नियम से ऊपर हैं। मैं साफ कर दूं कि ऐसा नहीं है। ये नियम मुझे विरासत में मिले हैं और इन्हें पालन करना अनिवार्य है।

चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों न हों, नियम 372 के तहत उन्हें पहले अध्यक्ष से अनुमति लेना अनिवार्य है। जब कोई सदस्य इस सदन की मर्यादा के खिलाफ जाते हैं तो मुझे कठोर निर्णय लेने की व्यवस्था देनी पड़ती है। नियमों के तहत किसी भी सदस्य को सदन में बोलने की आजादी तो है, लेकिन नियमों की सीमा में रहकर। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने माइक बंद करने का आरोप लगाया। चेयर के पास माइक बंद करने का बटन नहीं होता। विपक्ष में कई लोग इस चेयर पर बैठते हैं, उन्हें इसके बारे में पता है।

सभी महिला सदस्यों ने अपनी बात रखी

ओम बिरला ने कहा कि महिला सदस्यों को लेकर भी आरोप लगाया गया कि उन्हें मौका कम दिया जाता है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे कार्यकाल में सभी महिला सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। बजट पर चर्चा के दौरान कुछ महिला सदस्यों ने ट्रेजरी बेंच की तरफ जाकर नारेबाजी करने की कोशिश की। यह अप्रत्याशित घटना थी, इसलिए मैंने सदन में सत्ता पक्ष के नेता को सदन में न आने का आग्रह किया। मेरी कोशिश रहती है कि भले ही देर रात तक बैठना हो, मैं सबके बोलने के बाद ही सदन से जाता हूं। मुझे खुशी है कि जो भी सदन में बोलना चाहता था, उसे एक साल के अंदर ही मैंने बोलने का मौका दिया। निलंबन का विषय भी कुछ सदस्यों ने उठाया है। मेरा दल से ऊपर उठकर सभी सदस्यों से व्यक्तिगत संबंध आज भी है। लेकिन सदन की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मेरी है। हमें विचार करना होगा कि इस सदन को निलंबन जैसे कठोर निर्णय क्यों लेने पड़े। मैं अक्सर आग्रह करता हूं कि सदन की गरिमा बनी रहे। लेकिन जब सदन के सदस्य नहीं मानते, तो सदन स्थगित करना पड़ता है।

संसद में उठा फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग का मुद्दा- खरगे के तीखे सवाल, नड्डा बोले- विपक्ष के ऐसे बयान निंदनीय

नई दिल्ली । नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले का मुद्दा संसद में उठा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाए कि फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा खतरे है और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राय का दर्जा नहीं दिया जाना इसका प्रमुख कारण है। हालांकि, कांग्रेस के आरोपों और फारूक अब्दुल्ला पर हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन में जवाब दिया।

खरगे ने फारूक अब्दुल्ला पर हमले का मुद्दा उठाया

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा फारूक अब्दुल्ला पर हमला हुआ है। उनकी सुरक्षा खतरे में है। जम्मू-कश्मीर को राय का दर्जा था।

अब वहां की पुलिस और सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री के पास होने से आज जम्मू-कश्मीर में ऐसी हालत है। जम्मू-कश्मीर से कानून व्यवस्था खत्म हो रही है और प्रमुख नेताओं को मारने का मंसूबा है। फारूक अब्दुल्ला को भी इस तरह मार दिया गया होता। उनके सुरक्षाकर्मियों ने उनकी जान बचाई। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का फारूक अब्दुल्ला को मारने का इरादा है। अगर उनको सुरक्षित रखना चाहते थे, तो फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा

कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राय का दर्जा दिए जाने के बाद ही लोग सुरक्षित रह सकते हैं। केंद्र सरकार के हाथ में कश्मीर के लोग सुरक्षित नहीं है। क्योंकि सरकार का एक मंसूबा है कि जो लोग धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और देश को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खत्म करना है।

हमला चिंता का विषय, घटना की पूरी जांच की जाएगी- जेपी नड्डा

इस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा बुधवार रात फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ। यह बहुत ही चिंता का विषय है और गंभीर मामला है। भारत सरकार इस घटना को लेकर बहुत गंभीर है। मैं सरकार की ओर से इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि इस घटना की पूरी जांच की जाएगी। गिरफ्तार आरोपी के मंसूबों के बारे में गहराई से पता किया जाएगा। इस तरह की घटना दोबारा न हो और फारूक अब्दुल्ला के जीवन की रक्षा से जुड़ा हर कदम जरूर उठाया जाएगा। इसी बीच, जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खरगे के आरोपों को लेकर कांग्रेस की निंदा करते हुए कहा कि हर घटना को राजनीतिक चश्मे से देखना और उसे राजनीतिक रूप देना उचित नहीं है। पूर्व राय का दर्जा नहीं मिला, इस कारण यह घटना हुई, इस निष्कर्ष पर पहुंचना और सरकार पर गंभीर आरोप लगाना निंदनीय है।

जेपी नड्डा ने अपने जवाब में आगे कहा कि विपक्ष के नेता की ओर से यह कहना कि सरकार का मंसूबा उनको (फारूक) की जान लेना है। इस पर मेरा कहना है कि यह कांग्रेस की सोच का नतीजा है। हमेशा से कांग्रेस के मंसूबे इसी तरह के रहे हैं। विपक्ष ने सरकार के समय जम्मू-कश्मीर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदिग्धास्पद मौत पर कभी जवाब नहीं दिया।

राजीव शुक्ला ने भी हमले की निंदा की

वहीं कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने भी हमले की निंदा की और कहा कि फारूक अब्दुल्ला पर हमला निंदनीय है। हमलावर, जो जम्मू का जाना-पहचाना व्यक्ति है, ने खुद स्वीकार किया कि वह पिछले 20 वर्षों से उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय नेता पर यह हमला खतरनाक संकेत है।

डॉ. फारूक पर फायरिंग कर जान लेने की कोशिश, बाल-बाल बचे

गौरतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे कनपटी से सटाकर पिस्टल से फायरिंग कर उनकी जान लेने की कोशिश की गई। डॉ. फारूक बाल-बाल बच गए। एनएसजी कमांडो से अगर चंद सेकंड की भी देरी होती तो कुछ भी हो सकता था। हमला उस वक्त हुआ जब वे जम्मू के ग्रेटर कैलाश स्थित रॉयल पार्क में एक शादी समारोह में शिरकत करने के बाद उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के साथ वापस लौट रहे थे। जम्मू के पुरानी मंडी निवासी हमलावर कमल सिंह जम्वाल को मौके पर ही दबोच लिया गया।

इंस्टाग्राम पर कट्टा लहराकर बनाता था रील, ऑपरेशन 'शस्त्र' के दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी से दबोचा

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ रील और वीडियो पोस्ट कर लोगों में दहशत फैलाने वाले एक बदमाश को बुराड़ी थाना पुलिस ने 'ऑपरेशन शस्त्र' के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से एक कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार बुराड़ी थाना पुलिस को 'ऑपरेशन शस्त्र' के तहत विशेष रूप से ऐसे अपराधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए थे, जो पहले आर्म्स एक्ट या अन्य गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हैं इसी क्रम में हेड कांस्टेबल रोहित और हेड कांस्टेबल सचिन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध हथियार के साथ रील और पोस्ट डालने वालों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान पुलिस को एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक युवक की फोटो मिली, जिसमें वह हाथ में कट्टा लेकर फोटो पोस्ट कर रहा था। स्थानीय खुफिया तंत्र, मुखबिरों और तकनीकी निगरानी के जरिए युवक की पहचान अमृत विहार, बुराड़ी निवासी दीपक उर्फ झुमरी के रूप में हुई। सूचना के आधार पर तीन और चार मार्च की दरम्यानी रात को हेड कांस्टेबल रोहित और सचिन ने आरसीमी रोड, ट्रांसपोर्ट ऑफिस बुराड़ी के पास से दीपक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होना चाहता था। इसी मकसद से उसने अपने एक परिचित हिमांशु से देसी कट्टा लिया था और उसके साथ इंस्टाग्राम पर रील और वीडियो पोस्ट करने लगा। उसने यह भी बताया कि वह इन पोस्ट के जरिए गैंगस्टरों के संपर्क में आकर पैसा कमाना चाहता था। पुलिस के अनुसार आरोपित दीपक उर्फ झुमरी (26) पहले भी स्वरूप नगर थाने में दर्ज चोरी के तीन मामलों में शामिल रहा है। फिलहाल पुलिस अवैध हथियार सप्लाई करने वाले व्यक्ति की तलाश में जुटी है और मामले की आगे की जांच जारी है।

केवल इनकम के आधार पर ओबीसी क्रीमी लेयर का दर्जा नहीं,यूपीएससी में नियुक्तियों पर अदालत से राहत

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के क्रीमी लेयर से जुड़े मुकदमे में अहम टिप्पणी की। दो जजों की खंडपीठ ने आज अपने फैसले में कहा कि आरक्षण के इस मामले में अभ्यर्थी के क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल माता-पिता या अभिभावकों की सैलरी के आधार पर नहीं किया जा सका। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में सरकार की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि क्रीमी लेयर दर्जा का निर्धारण करते समय माता-पिता या अभिभावकों के पदों और स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बेंच ने केंद्र सरकार की उन अपीलों को खारिज कर दिया, जो हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ थीं। कोर्ट ने उन यूपीएससी उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद नौकरी नहीं दी गई थी। सरकार ने उनके माता-पिता की सैलरी को आधार मानकर उन्हें गलत तरीके से क्रीमी लेयर की श्रेणी में डाल दिया था। अदालत ने साफ किया कि अधिकारियों ने उम्मीदवारों को आरक्षण से बाहर करने के लिए गलत पैमाना अपनाया। जस्टिस महादेवन ने फैसले में लिखा कि कोई उम्मीदवार क्रीमी लेयर में आता है या नहीं, इसका फैसला केवल आय के आधार पर नहीं हो सकता। यह पूरा विवाद उन उम्मीदवारों से जुड़ा था जिनके माता-पिता सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू), बैंकों या इसी तरह के संस्थानों में काम करते थे। सरकार ने 2004 के एक स्पष्टीकरण पत्र का सहारा लेकर उनकी सैलरी को आय में जोड़ दिया था। इस वजह से वे आरक्षण के लाभ से वंचित हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के सरकारी आदेश का हवाला दिया। यह आदेश इंदिरा साहनी मामले के बाद बना था। इसमें स्पष्ट है कि क्रीमी लेयर तय करने के लिए माता-पिता का पद (जैसे ग्रुप ए या ग्रुप बी अधिकारी) मुख्य आधार है। इस नियम के तहत सैलरी और खेती से होने वाली कमाई को आय/संपत्ति टेस्ट में शामिल नहीं किया जाता। कोर्ट ने कहा कि 2004 का एक पत्र मुख्य नीति को नहीं बदल सकता। अदालत ने यह भी पाया कि सरकारी कर्मचारियों और पीएसयू कर्मचारियों के बीच भेदभाव करना गलत है। अगर सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पद के आधार पर छूट मिलती है, तो पीएसयू कर्मचारियों के बच्चों को केवल सैलरी के आधार पर आरक्षण से बाहर करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह 6 महीने के भीतर इन उम्मीदवारों के दावों पर फिर से विचार करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जरूरी हो तो इन उम्मीदवारों को नौकरी देने के लिए अलग से पद बनाए जाएं।

एलपीजी संकट पर प्रियंका गांधी का पीएम मोदी को जवाब- उम्मीद है आप सही हों, लेकिन ऐसा लगता नहीं

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों से घबराहट न करने का आग्रह करने और यह कहने के एक दिन बाद कि भारत कोविड महामारी की तरह ही एलपीजी सिलेंडर संकट से उबर जाएगा, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि पीएम मोदी सही हैं, लेकिन स्थिति पर संदेह व्यक्त किया। देशव्यापी एलपीजी की कमी की खबरों के बीच पीएम मोदी के आश्वासन पर कांग्रेस सांसद ने पत्रकारों से संक्षेप में कहा कि मुझे उम्मीद है कि वह सही हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले दिनों में एलपीजी की समस्या और गंभीर हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नागरिकों के हितों और ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। गांधी ने कहा कि सभी ईंधन एक समस्या बनने जा रहे हैं क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। दोषपूर्ण विदेश नीति ने यह समस्या पैदा की है।

अब हमें तैयारी करनी होगी। हमारे पास अभी भी थोड़ा समय बचा है। सरकार और प्रधानमंत्री को तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए; अन्यथा करोड़ों लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। विपक्ष के नेता ने आगे कहा कि ईरान ईंधन की आपूर्ति करेगा या नहीं, यह उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। यह युद्ध मूल रूप से मौजूदा विश्व व्यवस्था से जुड़ा है। हम एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय में आपको अपनी सोच बदलनी होगी। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अब उन्हें गहराई से सोचना शुरू करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे लोगों को भारी नुकसान न हो। यह कोई राजनीतिक बयान नहीं है। मुझे एक बड़ी समस्या आती दिख रही है। समस्या यह है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। इसका एक कारण है, और वह यह है कि वे एक जाल में फंस गए हैं। फिर भी, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत के लोग सुरक्षित रहें और हमारी ऊर्जा सुरक्षा का प्रबंधन हम स्वयं करें। प्रधानमंत्री एक जाल में फंसने के कारण प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं। फिर भी, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत के लोग सुरक्षित रहें। इंडिया गुट के नेताओं ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच एलपीजी की कथित कमी पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कमी की खबरों पर चर्चा का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि संसद जनता को आश्वस्त करने और ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने का मंच है।

नैन्सी ग्रेवाल की हत्या कट्टरपंथियों की कायराना हरकत

कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर नैन्सी ग्रेवाल जो कि पिछले लम्बे समय से खालिस्तानियों के खिलाफ बिना किसी खौफ के खुलकर बोला करती थी उनकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। सूत्र बताते है कि उनके पेट में 20 से अधिक बार चाकू से वार किए गए, उनकी जीभ काटी गई जिससे उनकी आंतड़ियां तक बाहर आ गई। उनकी मौत के बाद जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही है जिसमें मौत के लिए जिम्मेवार उनके मित्र को ठहराया जा रहा है और कुछ लोग डेरा राधा स्वामी के किसी अनुयाई के द्वारा इस घटना को अन्जाम देने की बात कर रहे है, क्योंकि नैन्सी ने अपनी आखिरी वीडियो में डेरा राधा स्वामी मुखी गुरिन्दर सिंह ढिल्लो के बारे काफी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। नैन्सी को डेरा मुखी का विक्रम सिंह मजीठिया से जाकर मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, उनका मानना था कि डेरा मुखी जिसे लाखों करोड़ों लोग अपना भगवान मानते है वह अगर किसी ऐसे व्यक्ति से जिस पर आपराधिक मामला दर्ज हो उसे जेल में मिले यह उनके अनुयायों के मन को ठेस पहुंचाता है। एक ओर संसार अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाकर महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा है और दूसरी ओर एक महिला जो अपने विचारों से देश के दुश्मनों के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करती थी उसकी निर्मम हत्या ने ना सिर्फ भारतीय समुदाय को बल्कि पूरे लोकतांत्रिक विश्व को झकझोर दिया है। नैन्सी की मां ने हत्या के लिए खालिस्तानियों को ही जिम्मेवार ठहराया है, उन्होंने साफ कहा कि उनकी बेटी को अनेकों बार खालिस्तानी धमकियां देते आ रहे थे जिसके चलते उन्होंने अपनी बेटी से ऐसा ना करने के लिए कहा था मगर वह बेखौफ होकर अपनी आवाज करोड़ों देशवासियों तक पहुंचाती रही और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी बेटी भले ही आज इस दुनिया में ना हो, पर आने वाले समय में नैन्सी जैसी और बेटियां निकलकर आएंगी। वैसे नैन्सी की मां बेटी की मौत से काफी डरी हुई है, ऐसा लगता है जैसे वो कातिलों के बारे में जान चुकी है, पर खौफ से नाम उजागर नहीं कर रही। नैन्सी के समर्थन में बोलने वालों को भी धमकियां मिल रही है जिससे उनकी मां को लगता है कहीं उन्हें भी मौत के घाट न उतार दें। वहीं दूसरी ओर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए नैन्सी की हत्या के लिए भारतीय हुकूमत और एजेंसियों को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। ऐसी घटनाओं का उद्देश्य अक्सर केवल एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि एक व्यापक संदेश देना भी होता है कि जो भी अलगाववादियों के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसका यही अंजाम होगा। यह भय पैदा करने की रणनीति होती है जिससे समाज में आत्म-संयम और चुप्पी का माहौल बन जाए लेकिन इतिहास गवाह है कि विचारों को हिंसा से कभी नहीं दबाया जा सकता। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की है। नैन्सी ग्रेवाल की हत्या एक गहरी पीड़ा और चिंता का विषय है। यदि यह घटना विचारों की असहिष्णुता और कट्टरपंथ से जुड़ी है तो यह स्पष्ट रूप से उस मानसिकता की कायरता को दर्शाता है जो बहस और लोकतांत्रिक संवाद से डरती है। गुरु नानक पब्लिक स्कूल की छात्रा बनी अमरीकी राष्ट्रपति की दुभाषिया - पश्चिमी दिल्ली के गुरु नानक पब्लिक स्कूल की छात्रा गुरदीप कौर चावला ने अमरीकी राष्ट्रपति के साथ दुभाषिये के तौर पर काम करते हुए, जहां समूचे सिख कौम और भारत देश के गौरव को बढ़ाया वहीं गुरु नानक पब्लिक स्कूल का नाम भी संसार भर में रोशन किया है। उन्हें इस बात का गर्व है कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गुरु नानक पब्लिक स्कूल से हासिल की। वह उन क्षणों को और अपने टीचर्स, मैनेजमेंट को सदा याद रखती है जिनके कारण वह आज इस मुकाम तक पहुंच सकी है। स्कूली शिक्षा के बाद वह पहली बार अपने स्कूल लौटी थी। आपको बता दें कि मौजूदा समय में वह कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के इंडिया आए डेलिगेशन का हिस्सा है। स्कूल के संरक्षक सरदार हरमनजीत सिंह, चेयरमैन बलदीप सिंह राना, मैनेजर जगजीत सिंह, स्कूल की प्रिंसिपल मनप्रीत कौर ने उनका शानदार स्वागत किया और बच्चों को उनसे प्रेरणा लेने की सलाह दी। गुरदीप कौर चावला ने साबित कर दिया कि स्कूल में अध्यापक सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा देते है और उनमें से कुछ बच्चे गंभीरतापूर्वक पढ़ाई करते हुए उच्च मुकाम हासिल करने में सफलता हासिल कर लेते हैं। गुरदीप कौर चावला ने दावा किया कि अमृत छकने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर दुनिया भर के नेताओं की कूटनीतिक बातचीतों के दौरान उनकी आवाज बनना और सही भाषाई मतलब निकालना बहुत मुश्किल लेकिन लाजवाब काम है जो गुरदीप कौर के द्वारा बाखूबी निभाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने सिख भावनाओं को समझा - सिख कौम के लिए जो कार्य मौजूदा केन्द्र की सरकार कर रही है शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से लेकर समूस मंत्रिमण्डल सिख गुरुओं की कुर्बानियों से भलिभान्ति वाकिफ है। इसी के चलते एक-एक करके सिखों की मांगों को पूरा किया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ हालांकि भारत के रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं, बावजूद इसके सिख श्रद्धालुओं के जत्थे को पाकिस्तान स्थित गुरधामों के दर्शनों की मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाना इसका पुख्ता सबूत है। मगर पाकिस्तान अपनी ओछी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, उसके द्वारा जानबूझ कर भारत से अलग हटकर पाकिस्तान में प्रवेश की तिथि दी जाती है। इस बार भी भारत के द्वारा 12 अप्रैल तय की गई मगर पाकिस्तान ने 10 तारीख का ऐलान कर दिया जो कि निन्दनीय है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के सलाहकार और विदेश नीतियों के माहिर परमजीत सिंह चंडोक की पाकिस्तान सरकार से ऐसी दुविधाओं को दूर करने की अपील भी की गई है।

अमरीका की कूटनीति नहीं दादागिरी!

आज दुनिया में हर और युद्ध, तबाही और अराजकता का दौर है। विकास की गति रुक रही है। अनिश्चितता का वातावरण है। अनेक देशों के नेता तो मवालियों की तरह बर्ताव कर रहे है। जबकि विश्व के लोग हमेशा शांति और विकास चाहते हैं। इस उठा-पटक में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सबसे आगे हैं। ट्रम्प ही क्यों, अमरीका की तो फितरत ही रही है कि कोई बहाना ढूंढ कर कमजोर देशों को दबाना और उनके संसाधनों पर कब्जा करना। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हुई, जिसमें लिखा है कि "प्रिय दुनिया, क्या तुम अमरीका और उसके सहयोगियों द्वारा झूठ बोलने से थक नहीं गए हो क्या तुम उस साम्राज्य से थक नहीं गए, हो, जो खून और मौत की तलाश में नहीं रुकता अमरीका या उसके सहयोगी कभी किसी बात पर सच्चे रहे है दुनिया कब इनके झूठ से ऊब जाएगी अब तो हमें पता होना चाहिए कि वैश्विक अशांति, मौत, अराजकता और विनाश के जिम्मेदार कौन है जो दुनिया की स्थिरता के खिलाफ है जो विश्व शांति के विचार से डरते है तुम्हारी चुप्पी सहयोग है। अमरीका वैश्विक मुसीबत पैदा करने वाला है। मौत और विनाश की मशीन! अमरीकी साम्राज्य की तानाशाही के खिलाफ बोलो!!!" यह पोस्ट न केवल अमरीका की ऐतिहासिक गलतियों को उजागर करती है बल्कि दुनिया को जगाने का प्रयास भी करती है। आज, जब हम वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान जैसे देशों में अमरीकी हस्तक्षेप की नई लहर देख रहे है, यह स्पष्ट हो गया है कि अमरीका के फैसले गलत साबित हो चुके है। इन युद्धों ने न केवल लाखों जानें लीं, बल्कि दुनिया को अस्थिरता की ओर धकेला। अमरीका की इन गलतियों से यह पता चलता है कि वैश्विक समुदाय अब युद्धों से कितना ऊब चुका है अमरीका की विदेश नीति का इतिहास झूठ, हस्तक्षेप और युद्धों से भरा पड़ा है। 1950 के दशक से शुरू करें तो कोरियाई युद्ध (1950-1953) में अमरीका ने उत्तर कोरिया के आक्रमण का बहाना बनाकर हस्तक्षेप किया लेकिन वास्तविकता यह थी कि यह शीत युद्ध की रणनीति का हिस्सा था। लाखों कोरियाई मारे गए लेकिन क्या अमरीका की जीत हुई नहीं, यह युद्ध आज भी कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव का कारण बना हुआ है। इसी तरह, 1954 में ग्वाटेमाला में अमरीका ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फैंका, क्योंकि वहां की भूमि सुधार नीतियां अमरीकी कंपनियों को पसंद नहीं आई। ग्वाटेमाला आज भी गरीबी और हिंसा से जूझ रहा है। 1950-60 के दशक में अमरीका के झूठ की फेहरिस्त लंबी है। इंडोनेशिया (1958) में सी.आई.ए. ने विद्रोहियों को समर्थन दिया लेकिन असफल रहा। क्यूबा (1961) में 'बे ऑफ पिग्स' हमला एक बड़ी असफलता थी, जहां अमरीका ने फिदेल कास्त्रो को हटाने की कोशिश की लेकिन खुद की किरकिरी हुई। वियतनाम युद्ध (1961-1975) तो अमरीकी इतिहास का सबसे काला अध्याय है। अमरीका ने 'टोंकिन की खाड़ी घटना' को बहाना बनाकर युद्ध शुरू किया, जो बाद में झूठ साबित हुआ। 58,000 अमरीकी सैनिक और लाखों वियतनामी मारे गए। अमरीका हारकर लौटा, और वियतनाम आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है। लाओस (1964-1973) और कंबोडिया (1969-1970) में गुप्त बमबारी ने लाखों लोगों को मार डाला और खमेर रूज जैसी आतंक को जन्म दिया। कांगो (1964) में अमरीका ने वहां प्रधानमंत्री पैट्रिस लुमुम्बा की हत्या में भूमिका निभाई, जो अफ्रीका की आजादी के प्रतीक थे। डोमिनिकन रिपब्लिक (1965) में हस्तक्षेप ने लोकतंत्र को कुचला। 1980 के दशक में भी यह सिलसिला जारी रहा। ग्रेनाडा (1983) में अमरीका ने मैडिकल छात्रों की सुरक्षा का बहाना बनाकर आक्रमण किया लेकिन यह छोटे देश पर साम्राज्यवादी कब्जा था। लेबनान (1983-1984) में अमरीकी सैनिकों की मौत हुई लेकिन कोई स्थायी शांति नहीं आई। लीबिया (1986) में गद्दाफी पर हमला, ईरान (1987-1988) में नौसेना संघर्ष, पनामा (1989) में नोरिएगा को हटाना-ये सभी फैसले अमरीका की ताकत दिखाने के लिए थे लेकिन उन्होंने क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाई। इराक के खिलाफ 1991 का गल्फ वॉर, 1998 की बमबारी और 2003 का आक्रमण "महाविनाश के हथियारों" के झूठ पर आधारित था। सद्दाम हुसैन को हटाया गया लेकिन इराक आज भी अराजकता में डूबा है, आई.एस.आई.एस. जैसे समूह पैदा हुए। सोमालिया (1992-1994, 2007-वर्तमान) में अमरीकी हस्तक्षेप ने समुद्री डकैती और आतंकवाद बढ़ाया। बोस्निया (1994-1995) में नाटो हमले, सूडान (1998) में दूतावास बमबारी, अफगानिस्तान (1998, 2001) में तालिबान के खिलाफ युद्ध-ये सभी अमरीका की 'आतंकवाद विरोधी' नीति के नाम पर थे, लेकिन अफगानिस्तान से 2021 की शर्मनाक वापसी ने साबित किया कि 20 साल का युद्ध व्यर्थ था। यूगोस्लाविया (1999) में नाटो बमबारी ने कोसोवो को अलग किया, लेकिन जातीय तनाव आज भी है। यमन (2002-वर्तमान) में ड्रोन हमलों ने नागरिकों को मार डाला, पाकिस्तान (2004) में भी यही हुआ। सीरिया (2014) में आई.एस.आई.एस. के खिलाफ हस्तक्षेप ने देश को बर्बाद कर दिया। लीबिया (2011) में गद्दाफी को हटाने के बाद देश गृहयुद्ध में फंस गया। और अब 2026 में वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान पर झूठ। वेनेजुएला में अमरीका ने दावा किया कि मादुरो तानाशाह है, लेकिन यह तेल संसाधनों पर कब्जे की कोशिश है। क्यूबा पर दशकों से प्रतिबंध, लेकिन 2026 में नए आरोप लगाकर दबाव बढ़ाया जा रहा है। ईरान पर परमाणु कार्यक्रम के बहाने हमले की धमकी, जबकि ईरान शांति समझौते चाहता है। ये सभी फैसले गलत साबित हो चुके है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स बताती है कि युद्धों से करोड़ों लोग विस्थापित हुए, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं। यूक्रेन-रूस संघर्ष और इसराईल-फिलिस्तीन विवाद में अमरीका की भूमिका ने दिखाया कि वह शांति दलाल नहीं, बल्कि युद्ध उकसाने वाला है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के देश अब चीन और रूस जैसे भागीदारों की ओर मुड़ रहे है,

सम्पादकीय...

सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में क्रांतिकारी एचपीवी वैक्सीन

सर्वाइकल कैंसर विश्व स्तर पर महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसरों में से एक है, जिसके प्रतिवर्ष लगभग 660,000 नए मामले सामने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में 14 वर्षीय लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया, जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर सहमति के बाद स्वैच्छिक, निःशुल्क, एकल खुराक एचपीवी वैक्सीन दी जाएगी। डब्ल्यूएचओ से जुड़े क्षेत्रों में दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र का गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की घटनाओं (नये मामलों) और मृत्यु दर में दूसरा सर्वोच्च स्थान है, जिसमें भारत का योगदान 65 फीसदी से ऊपर है। भारत में महिलाओं में यह दूसरा सबसे आम कैंसर है, जिसके बारे में अनुमान लगाया गया कि साल 2022 में देश में 127,526 नये मामले सामने आये और इससे 79,906 मौतें हुई। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच का विस्तार चिंताजनक रूप से निम्न है और 30-49 साल की केवल 1.9 फीसदी महिलाओं की जांच की जा रही है। हालांकि, एचपीवी वैक्सीन के काले अतीत को भुलाया नहीं जा सकता। साल 2009-10 में आंध्र प्रदेश और गुजरात में एक परीक्षण का हिस्सा रही सात लड़कियों की मौत हो गयी थी। आईसीएमआर की जांच में दावा किया गया कि जो कारण थे वो शायद वैक्सीन से जुड़े नहीं थे। हालांकि, इन सभी मामलों में मौत की वजह पक्के तौर पर स्थापित नहीं की जा सकती। इसने सभी एईएफआई की पहचान करने और उनकी छानबीन करने की जरूरत की ओर भी एक प्रमुख चिंता के रूप में ध्यान दिलाया। भारत द्वारा 14 वर्षीय लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का कदम ऐसे समय में विज्ञान के समर्थन में सशक्त संदेश है जब पूरी दुनिया में टीकाकरण-विरोधी भावनाएं खतरनाक रूप से तेजी पकड़ रही हैं। टीकों से परहेज का असर अमेरिका में साफ दिख रहा है जहां वर्तमान में 26 राज्यों में खसरा की महामारी पांव पसार रही है। एचपीवी टीकाकरण केवल निर्धारित सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में और प्रशिक्षित स्वास्थ्य अधिकारियों की मौजूदगी में संचालित किया जायेगा। साथ ही, कुशल स्वास्थ्य-देखभाल टीमें वैक्सीन लगाने के बाद निगरानी और 'टीकाकरण के पश्चात होने वाली प्रतिकूल घटनाओं' (एईएफआई) से निपटने के लिए तैयार रहेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित एक खुराक वाली वैक्सीन इस्तेमाल में लायी जायेगी। इस बात के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर के लगभग सभी मामलों में एचपीवी की उच्च-जोखिम वाली किस्मों, खासकर 16 व 18, से लगातार संक्रमण ही कारण होता है। भारत में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के कुल मामलों में 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सा इन्हीं दोनों किस्मों का है। साक्ष्य इस तथ्य की ओर भी इशारा करते है कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को एचपीवी टीकाकरण और नियमित जांच के जरिए काफी हद तक रोका जा सकता है और अगर

हमारी विदेश नीति और प. एशिया तनाव

लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक की चेलसी नगोक मिन्ह ने लिखा है, भारत की प्रतिष्ठा ने कुछ ही महीनों में जो गिरावट आई है वह असाधारण है। अब फिर अमेरिका के उपविदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने कहा है कि भारत के मामले में हम वही गलती नहीं दोहराएंगे जो 20 साल पहले हमने चीन के मामले में की थी। हम भारत के बाज़ार को विकसित नहीं होने देंगे ताकि भारत हमें ही पीछे न छोड़ दे। इसे कहते है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है! बहुत कुछ समझ भी आ रहा है। हम पर दुनिया में सबसे अधिक 50फीसदी टैरिफ लगाया गया जबकि चीन हमसे भी अधिक तेल रूस से खरीदता है। अमेरिका हमारे उत्थान को 'मैनेज' करना चाहता है ताकि चीन की तरह हम एक दिन बड़ा प्रतिद्वंद्वी न बन जाएं। यही कारण भी है कि वह देश पाकिस्तान को इस तरह सिर पर उठा रहा है। इसका यह भी मतलब है कि हमने इस युद्ध में चाहे एक साइड को चुन लिया है, उस साइड ने हमें नहीं चुना। संसद में विदेश मंत्री जयशंकर में 'भारत की गहरी चिन्ता' और शान्ति की बात कही, पर इसमें नया क्या है रूसी तेल के बारे अमरीकी विदेश मंत्री ने जो कहा है उस पर विदेश मंत्री ने सीधा जवाब क्यों नहीं दिया उनके उपविदेशमंत्री की बदतमीज़ी का सीधा जवाब क्यों नहीं दिया गया ईरान पर हमले से चारों तरफ़ आर्थिक अफ़रा-तफ़री फैल रही है।

अमेरिका-इज़राइल और ईरान का युद्ध हिन्द महासागर की लहरों पर सवार हो कर हमारे दरवाज़े तक पहुंच चुका है। श्रीलंका के तट से 44 नॉटिकल मील दूर अमेरिका की पनडुब्बी द्वारा ईरान के युद्धपोत 'डेना' को टारपीडो से डुबोए जाने की घटना के बाद से भारत की भूमिका को लेकर देश और विदेश में बहुत चर्चा और आलोचना हो रही है। यह जहाज़ हमारा मेहमान था और विशाखापटनम में बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास में हिस्सा लेने के बाद लौट रहा था कि उसे डुबो दिया गया लेकिन हम तो इस युद्ध से तब से जुड़े हुए है जब से प्रधानमंत्री मोदी ने इज़राइल की यात्रा की थी। इस यात्रा की समाप्ति के कुछ ही घंटों के बाद ईरान पर हमला कर दिया गया। इज़राइल के विदेश मंत्री ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी को इसके बारे जानकारी नहीं दी गई। यह कूटनीतिक धोखा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि भारत और इज़राइल अच्छे मित्र हैं तो दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री को अंधेरे में रख कर उनकी स्थिति असुखद बना दी गई है। अमेरिकी- इज़राइली हमले में ईरान के आयतुल्लाह खामेनेई मारे गए। उनके शासन काल में ईरान का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पतन हुआ। पर यह उनका मामला है। वह उस देश के राष्ट्राध्यक्ष थे जिसके साथ हमारे प्राचीन सम्बन्ध हैं और पड़ोसी देश है। भारत सरकार ने तत्काल कोई शोक प्रकट नहीं किया जबकि अमेरिका और इज़राइल बहुत गलत परम्परा डाल रहे है। ऐसे में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष सुरक्षित नहीं रहेगा। कल को अगर रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर हमला करता है तो क्या वह भी जायज़ होगा भारत सरकार की चुप्पी पर चारों तरफ़ उठ रहे सवालों के पांच दिन बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ईरानी दूतावास भेजा गया जहां उन्होंने शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और संवेदना प्रकट की, पर किसी भी राजनीतिक नेता ने संवेदना प्रकट करने की औपचारिकता नहीं निभाई। फिर ईरानी युद्धपोत 'डेना' को डुबोने का मामला भड़क गया। वह जहाज़ हमारे पानी में नहीं था। वह तो श्रीलंका के पानी में भी नहीं था। उन्होंने खुद को बचाने का जो डिस्ट्रैस सिग्नल भेजा वह भी श्रीलंका को भेजा जिसने 130 में से 32 नौसैनिकों को बचा लिया। हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती, पर तकलीफ़देह सवाल ज़रूर उठते है। एक, क्या भारत को जानकारी थी कि हमारे पड़ोस में अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी शिकार की खोज में घूम रही है अगर हमें मालूम नहीं था तो और भी चिन्ता की बात है क्योंकि हम तो खुद को हिन्द महासागर का संरक्षक मानते है। विदेश मंत्री जयशंकर ने माना है कि, हां, हम हिन्द महासागर में सुरक्षा प्रदान करने वाला देश है। पर सागर अलग हक़ीक़त है। दूसरे देश भी यहां मौजूद है। वह तो खुद को काट रहे है। दूसरी बात है कि यह युद्धपोत और उसके नौसैनिक हमारे मेहमान थे। ईरान ने कहा भी है कि 'हम भारत के मेहमान थे'। पूर्व नौसेनाध्यक्ष एडमिरल अरुण प्रकाश का कहना है कि यह हमारी क्षेत्रीय विश्वसनीयता और रणनीतिक स्वायत्ता को धक्का है और वह कहते हैं कि हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस जहाज़ के बारे आवाज़ उठाएं जो हमारा मेहमान था। पर जयशंकर ने 'सागर की हक़ीक़त' कह कर मामला खत्म कर दिया। पूर्व विदेश सचिव विवेक काटजू की टिप्पणी है कि क्या अमेरिका को नाराज़ करने की सम्भावना हमारे कदमों को रोक रही है यही सवाल आज सारे देश में गूंज रहा है लेकिन अभी अमेरिका का अहंकार खत्म नहीं हुआ था। खाड़ी में युद्ध से तेल की कीमतों में भारी उछाल आ गया है। भारत तेल का बड़ा आयातक है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस पर यह विचित्र बयान दिया है कि, भारत बहुत अच्छा एक्टर रहा है। हमने उन्हें रूस से तेल लेना बंद करने को कहा तो उन्होंने ऐसा कर दिया। दुनिया में तेल की अस्थाई कमी को देखते हुए हमने उन्हें 30 दिन के लिए रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी है। अंग्रेज़ी के शब्द 'वेवर' अर्थात छूट का भी इस्तेमाल किया गया। भारत सरकार पहले तो चुप रही फिर अनाम सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि हम अपने फैसले खुद लेते है, पर 'अनुमति' या 'छूट' के बारे सीधा जवाब नहीं दिया। अमेरिकी अधिकारी कह रहे है कि भारत के फैसले नई दिल्ली में नहीं, वाशिंगटन में लिए जा रहे है पर नई दिल्ली शांत रही। कई महीनों से अमरीकी अधिकारी हमारी बेइज़्ज़त कर रहे है, पर हम जवाब नहीं दे रहे। लोग हैरान है और सोशल मीडिया में यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि क्या हमारी रणनीतिक स्वायत्ता बनावटी है यह तो नया डोनल्ड ट्रम्प का साम्राज्यवाद हम पर थोपने की कोशिश हो रही है। इसका डट कर मुक़ाबला होना चाहिए। सच्चाई है कि हमने सस्ता रूसी तेल लेना कम कर दिया और महंगा तेल ले रहे है यह भी समाचार है कि नाराज़ रूस अब सस्ता तेल नहीं देगा। एक समय था जब दुनिया में हमारी आवाज़ गूंजती थी। हम कमजोर थे, पर फिर भी अपनी बात कहने से गुरेज़ नहीं किया था। अब यह निराली चुप्पी लोगों को चुभ रही है। हम युद्ध के मामले में तटस्थ रहें तो समझ आता है, पर जब सीधा हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है फिर हम शांत क्यों रहते है एनर्जी अर्थशास्त्री डा. अनस अलहजो ने लिखा है, भारत जैसे महान देश को रूस से तेल लेने के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प से अनुमति लेने की क्या ज़रूरत है बहुत बुरी स्थिति है। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक की चेलसी नगोक मिन्ह ने लिखा है, भारत की प्रतिष्ठा ने कुछ ही महीनों में जो गिरावट आई है वह असाधारण है। अब फिर अमेरिका के उपविदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने कहा है कि भारत के मामले में हम वही गलती नहीं दोहराएंगे जो 20 साल पहले हमने चीन के मामले में की थी। हम भारत के बाज़ार को विकसित नहीं होने देंगे ताकि भारत हमें ही पीछे न छोड़ दे। इसे कहते है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है! बहुत कुछ समझ भी आ रहा है। हम पर दुनिया में सबसे अधिक 50फीसदी टैरिफ लगाया गया जबकि चीन हमसे भी अधिक तेल रूस से खरीदता है। अमेरिका हमारे उत्थान को 'मैनेज' करना चाहता है ताकि चीन की तरह हम एक दिन बड़ा प्रतिद्वंद्वी न बन जाएं। यही कारण भी है कि वह देश पाकिस्तान को इस तरह सिर पर उठा रहा है। इसका यह भी मतलब है कि हमने इस युद्ध में चाहे एक साइड को चुन लिया हो, उस साइड ने हमें नहीं चुना। संसद में विदेश मंत्री जयशंकर में 'भारत की गहरी चिन्ता' और शान्ति की बात कही, पर इसमें नया क्या है रूसी तेल के बारे अमरीकी विदेश मंत्री ने जो कहा है उस पर विदेश मंत्री ने सीधा जवाब क्यों नहीं दिया उनके उपविदेशमंत्री की बदतमीज़ी का सीधा जवाब क्यों नहीं दिया गया ईरान पर हमले से चारों तरफ़ आर्थिक अफ़रा-तफ़री फैल रही है। देश में एलपीजी का संकट खड़ा हो गया है। सबसे अफ़सोस की बात है कि जयशंकर का बयान संसद के उस नियम के अधीन दिया गया जिसमें उनसे विपक्ष सवाल नहीं पूछ सकता। सरकार कब तक सवालों से भागती रहेगी योरूप में ट्रम्प की नीतियों का विरोध शुरू हो गया है। विरोध का स्वर ऊंचा करने वालों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी है जिनके साथ ट्रम्प की ज़बरदस्त तू-तू, मैं-मैं चल रही है, जबकि दोनों देश घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं। समय आ गया है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपनी विदेश नीति की दिशा पर फिर से गौर करें। 'रणनीतिक खामोशी' कई मामलों में सही रहती है, पर तब नहीं जब हमारे हितों पर आंच आ रही हो या हमारी संप्रभुता और आत्मसम्मान पर वार किया जा रहा हो। हमें अपनी आवाज़ फिर से बुलंद करनी है, जहां तक अमेरिका का सवाल है, उनके पूर्व विदेश मंत्री हैनरी किसिंजर के यह शब्द याद रखने चाहिए कि, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, पर

यूसीसी लागू करने का सही समय

यह सवाल बार-बार उठा है कि जब आपराधिक मामलों में सभी समुदायों के लिए एक कानून का पालन होता है तब सिविल मामलों में सभी के लिए अलग-अलग कानून क्यों है कानूनों में बदलाव होते रहे हैं। अगर हिन्दू बिल नहीं लाया जाता तो न दहेज विरोधी कानून पास हो पाता और न ही सती प्रथा जैसी कुरीति का अंत हो पाता। जब भी इस मुद्दे पर आगे बढ़ा जाता है तो मुस्लिम संस्थाएं इसके विरोध में उतर आती हैं, जमकर राजनीति होती है और कहा जाता है कि यह कानून संविदान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। जिसमें कहा गया है कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है।

समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। देश में वर्ष 1961 में गोवा सरकार ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता कानून लागू किया था। एक देश में दो विधान क्यों चले इस पर राष्ट्रव्यापी बहस कई बार छिड़ चुकी है। भारत में इसे लागू करने की जरूरत 1985 की एक याचिका श्रीमती जॉर्डन डेंगे बनाम एस.एस. चोपड़ा मामले में महसूस हुई थी। श्रीमती जॉर्डन ईसाई थीं जबकि एस.एस.चोपड़ा सिख थे। इनके तलाक की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता लागू करने की पहली बार जरूरत जाहिर की थी। इसके बाद ऐसी कई याचिकाएं अदालतों में आई, बहुत चर्चित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि अब समान नागरिक संहिता लागू करने का समय आ गया है। शीर्ष अदालत ने 1937 के शरिया कानून के प्रावधानों को मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे निरस्त करने वाली याचिका पर यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यह बहुत अच्छा मामला है। सभी धर्मों की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक समान कानून की जरूरत महसूस की जा सकती है लेकिन इस पर केवल सरकार को ही विचार करना चाहिए। याचिका में मुस्लिम महिलाओं को विरासत और उत्तराधिकार में बराबर अधिकार दिलाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि फिलहाल मुस्लिम महिलाओं को अपने माता-पिता की सम्पत्ति में बहुत कम हिस्सा मिलता है जिसे बदलने की जरूरत है। पीठ ने यह भी चेताया कि अगर 1937 का शरिया कानून पूरी तरह से हटा दिया जाता है तोइससे कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है। अदालतें कानून नहीं बना सकतीं। इसलिए बेहतर होगा कि इस तरह के व्यापक कानून से जुड़े फैसले सरकार पर छोड़ देने चाहिए। समान नागरिक संहिता का विचार नया नहीं है। संविधान बनाने वालों ने इसकी कल्पना की थी और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की कोशिश करें। हालांकि अनुच्छेद 44 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में आता है, इसलिए इसे अदालतें सीधे लागू नहीं कर सकतीं। फिर भी यह इस संवैधानिक सोच को दर्शाता है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण जैसे मामलों से जुड़े नागरिक कानूनों को अंततः धार्मिक आधार पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के बजाय एक सामान्य कानूनी ढांचे के तहत लाया जाना चाहिए। यद्यपि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है, जहां पिछले वर्ष समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य भाजपा शासित राज्यों ने समान नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ाए हैं। सवाल है कि इस संबंध में केन्द्रीय स्तर पर कानून बनाने का। समान नागरिक संहिता में देशके प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होता है चाहे वह किसी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता का अर्थ धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर पूरे देश में एक समान कानून लागू करने से है।

समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन-जायदाद के बंटवारे और उत्तराधिकार गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे सभी एक कानून के अन्तर्गत आ जाते है। किसी धर्म के आधार पर कोई अलग कोर्ट या अलग व्यवस्था नहीं होती लेकिन भारत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां सभी धर्मों के लिए अलग-अलग नियम हैं। सम्पत्ति, विवाह, तलाक के नियम हिन्दुओं, मुस्लिमों, ईसाइयों के लिए अलग-अलग हैं। यह सवाल बार-बार उठा है कि जब आपराधिक मामलों में सभी समुदायों के लिए एक कानून का पालन होता है तब सिविल मामलों में सभी के लिए अलग-अलग कानून क्यों है कानूनों में बदलाव होते रहे हैं। अगर हिन्दू बिल नहीं लाया जाता तो न दहेज विरोधी कानून पास हो पाता और न ही सती प्रथा जैसी कुरीति का अंत हो पाता। जब भी इस मुद्दे पर आगे बढ़ा जाता है तो मुस्लिम संस्थाएं इसके विरोध में उतर आती हैं, जमकर राजनीति होती है और कहा जाता है कि यह कानून संविदान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। जिसमें कहा गया है कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। परिवार और उत्तराधिकार के विषय संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं। इसलिए राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने राज्य के नागरिकों के लिए एक समान कानून बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणियां एक बार फिर यह याद दिलाती हैं कि संवैधानिक वादे को वास्तविकता में बदलने का समय आ चुका है। समानता के सिद्धांत पर चलने वाले लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्थाओं को नहीं बनाए रखा जा सकता जो धार्मिक पहचान के आधार पर मुस्लिम महिलाओं से गैर बराबरी का व्यवहार करता हो। समान नागरिक संहिता की दिशा में लगातार संवाद के साथ कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि ऐसा कानूनी ढांचा तैयार हो सके जिस पर व्यापक सहमति हो। समान नागरिक संहिता महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। साथ ही इसकी एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को बल मिलेगा। इससे कई विवाद अपने आप हल हो जाएंगे और इसके लागू होने से नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, इबादत, खान-पान और धार्मिक परम्पराओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार पाहो ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीमतपुरा एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार पाहो, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/0882)

भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही नारी को ऊंचा स्थान- संजय

महिलाएं लिख रहीं समाज के सशक्तिकरण की सफल कहानी- महेश

निर्वाण सेवा संस्थान, कुशीनगर द्वारा शैक्षणिक संगोष्ठी आयोजित

कसया, कुशीनगर।

नगरपालिका परिषद कुशीनगर क्षेत्र अंतर्गत महंथ अवैद्यनाथ नगर स्थित श्री दुर्गा जी इंटरमीडिएट कालेज, सिसवा - महंथ के परिसर में निर्वाण सेवा संस्थान, कुशीनगर द्वारा एक संगोष्ठी आयोजित कर नारी सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों पर चर्चा की गई। गुरुवार को विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे आयोजन क्रम में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता संजय सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही नारी को ऊंचा स्थान दिया गया है। उसके अनुरूप हमें बालिकाओं को संस्कार पूर्ण शिक्षा देने के लिए जागरूक होना होगा।

विद्यालय के प्रबंधक महेश पासवान ने कहा कि नारी अब अबला नहीं रही वह विज्ञान, शिक्षा, खेल, सुरक्षा, निर्माण सहित विविध क्षेत्रों में आगे है और राष्ट्र, परिवार व समाज के सशक्तिकरण की सफल कहानी लिख रही हैं। श्रीमती सरिता ने महिला अधिकार पर चर्चा की। आयोजक संस्था की ओर से कार्यक्रम संयोजक हृदया नन्द शर्मा ने विद्यालय के प्रबंधक महेश पासवान सहित अतिथियों को अंग वस्त्र, बुद्ध की प्रतिमा, डायरी, लेखनी प्रदान कर सम्मानित किया। संस्थान के प्रबंधक/मुंबई हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विजेंद्र कुमार राय के निर्देशन में सुखी, खुशहाल राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ विविध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस दौरान शिक्षक विक्रम कुमार भारती, रमेश प्रसाद, हिमांशु शर्मा, अभिषेक सिंह, गंगा शर्मा, अंश पासवान, भुअर पटेल, कुसुम, आस्था, श्रेया, लाडो, अंभिका, काजल, अमन सहित छात्र - छात्राएं मौजूद रहे।

बुद्ध का मध्यमार्ग और आज का समाज विषय पर गोष्ठी संपन्न

बुद्ध के उपदेश विश्व के लिए कल्याणकारी-प्राचार्य डॉ. रवि शंकर राव

कसया, कुशीनगर।

दुलारी सेवा संस्थान, कुशीनगर के तत्वावधान में बुद्ध का मध्यमार्ग और आज का समाज विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन नगर के निरंकारी इंटरमीडिएट कॉलेज में संपन्न हुआ। वक्ताओं ने भगवान बुद्ध के उपदेश करुणा, मैत्री और शांति को विश्व के लिए कल्याणकारी बताया। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम के मुख्यअतिथि प्राचार्य सरदार पटेल महाविद्यालय डॉ. रवि शंकर प्रताप राव ने कहा कि बुद्ध का मध्यमार्ग जीवन में संतुलन, संयम और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि आज के भौतिकवादी और तनावपूर्ण वातावरण में भगवान बुद्ध के विचार समाज को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। मुख्य वक्ता शिक्षक राजू कुमार मद्धेशिया ने बताया कि मध्यमार्ग व्यक्ति को अतिरेक से बचाकर सदाचार, करुणा और नैतिक मूल्यों की ओर प्रेरित करता है।

वर्तमान समय में बढ़ती सामाजिक चुनौतियों के बीच बुद्ध का दर्शन अत्यंत प्रासंगिक है। विशिष्ट अतिथि गविश उपाध्याय ने युवाओं को बुद्ध के सिद्धांतों को आत्मसात करने का आह्वान किया, जिससे एक सशक्त एवं नैतिक समाज का निर्माण हो सके।

अंत में संस्था के सचिव अमित मिश्रा ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। गोष्ठी में रमेश मद्धेशिया, पवन गुप्ता, धीरज जायसवाल, रामप्रताप चौरसिया, कृष्ण मुरारी धर द्विवेदी सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे।

हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं सकुशल संपन्न

कुशीनगर। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2026 जनपद कुशीनगर में शांतिपूर्ण, शुचितापूर्ण एवं नकलविहीन वातावरण में सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा के सफल संचालन में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया कि परीक्षा के दौरान राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक, सभी सचल दलों के प्रभारी एवं सदस्य, जनपदीय तथा लाइव कंट्रोल रूम के प्रभारी व सदस्य, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। सभी के सहयोग और सतर्कता के कारण जनपद में परीक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से परीक्षा पूरी तरह शुचितापूर्ण वातावरण में संपन्न कराई गई ।

राजा देवी महिला पी.जी. कॉलेज में रोवर्स-रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर का द्वितीय दिवस संपन्न

प्रशिक्षुओं को प्राथमिक चिकित्सा, गांठ-बंधन व टोली प्रणाली का दिया गया प्रशिक्षण

भटनी देवरिया।

राजा देवी महिला पी.जी. कॉलेज, सझझपुर भटनी देवरिया में बी.एड. प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित पाँच दिवसीय स्काउट/ गाइड (रोवर्स-रेंजर्स) प्रशिक्षण शिविर का द्वितीय दिवस उत्साह, अनुशासन और सक्रिय सहभागिता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वज शिष्टाचार, प्रार्थना एवं झंडा गीत के साथ हुई। इसके पश्चात प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षुओं को स्काउट-गाइड के सिद्धांतों, नियमों तथा सेवा भावना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं। प्रशिक्षण सत्र में मुख्य प्रशिक्षक सूरज चंद तथा प्रशिक्षक शिवा कुमार एवं कु. संजल साहनी ने छात्राओं को टोली प्रणाली, प्राथमिक चिकित्सा, गांठ एवं बंधन (नॉट्स एंड लैशिंग), अनुशासन तथा सामूहिक कार्य की उपयोगिता के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। साथ ही विभिन्न खेल गतिविधियों और समूह अभ्यासों के माध्यम से प्रतिभागियों में नेतृत्व क्षमता, सहयोग की भावना और आत्मविश्वास विकसित करने पर जोर दिया गया महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अमित कुमार राय ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि रोवर्स-रेंजर्स प्रशिक्षण युवाओं में सेवा, अनुशासन और नेतृत्व की भावना को विकसित करता है। इससे छात्र-छात्राएं समाज के प्रति जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रशिक्षुओं ने पूरे उत्साह और सक्रियता के साथ सभी गतिविधियों में भाग लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त प्रवक्तागण एवं बी.एड. के प्रशिक्षु उपस्थित रहे। पाँच दिवसीय यह प्रशिक्षण शिविर आगामी दिनों में विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों, सामाजिक सेवा कार्यक्रमों तथा कैम्पफायर के साथ आगे भी जारी रहेगा।

गुमटी का ताला तोड़ चोरी करते पकड़ा गया युवक

कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कोटवा धुधली मार्ग पर स्थित बिहारी छपरा चौराहे पर स्थित पान की दुकान में गुमटी का ताला तोड़ चोरी कर रहे युवक को दुकानदार ने रंगे हाथों पकड़ पुलिस को सौंपा। बिहारी छपरा चौराहे पर खजुरी निवासी राजेश कुशवाहा की पान की और कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। बृहस्पतिवार की रात राजेश का लड़का धीरज दस बजे दुकान बंद कर चचेरे भाई के घर बहु भोज में खाना खाने घर गया था।घर से वापस आने पर देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है और दुकान में रखी कुर्सी पर एक युवक बैठा है और दुकान से पेय पदार्थ और पैसे खाने की चीजें गायब है।युवक को देख धीरज के शोर मचाने पर बगल के दुकानदार भी मौके पर पहुंच आए। युवक को पकड़ कर बैठा लिया। युवक के जेब की तलाशी के बाद उसके जेब से दो पैकेट सिगरेट, पान मसाले की पुड़िया और कुछ पैसे बरामद हुए । उसके बाद दुकानदार द्वारा पुलिस को सूचना दी गई मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस को युवक को सौंप दिया गया । पी आर वी पुलिस द्वारा सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा पकड़े गए युवक को थाने ले जाया गया। दुकानदार राजेश द्वारा बताया गया कि वह एल आई सी में एजेंट का काम करते है। एक किश्त का पैसा और दुकान की बिक्री का पैसा रखा था वह गायब है।

17 दिन, 4 जिले, 10-10 हजार का इनाम- फिर भी पुलिस के हाथ खाली

दबिश और सर्विलांस को ठेंगा दिखा रहे भगोड़े, बीएसए कार्यालय में संजीव-तनुज के पटल हटाए गए, नए लिपिकों की तैनाती से सिंडिकेट को झटका

देवरिया/गोरखपुर । शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या प्रकरण में मुख्य आरोपी पिछले 17 दिनों से कानून को चुनौती दे रहे हैं। निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और उनके खास बाबू संजीव सिंह की गिरफ्तारी में पुलिस की नाकामी ने अब खाकी की साख पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। 10-10 हजार रुपये का इनाम, चार जिलों में छापेमारी और सर्विलांस की निगरानी के बावजूद ये भगोड़े पुलिस की पकड़ से दूर हैं। गोरखपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच और विशेष टीमें पिछले कई दिनों से प्रयागराज, लखनऊ, बलिया और देवरिया में डेरा डाले हुए हैं। संजीव सिंह के आधा दर्जन से अधिक रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई, लेकिन शातिर आरोपियों ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। हर बार पुलिस का यह दावा कि जल्द गिरफ्तारी होगी, अब महज एक कागजी बयान बनकर रह गया है। सूत्र बताते हैं कि आरोपियों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वे पुलिस की हर रणनीति को विफल कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या पुलिस पर किसी ऊपरी दबाव का असर है या फिर विभाग के ही कुछ विभीषण आरोपियों को पल-पल की जानकारी दे रहे हैं? इधर, बेसिक शिक्षा विभाग ने भगोड़े आरोपियों की वापसी की उम्मीद छोड़ते हुए कार्यालय की व्यवस्था को पटरी पर लाना शुरू कर दिया है। प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बुधवार शाम को बड़ा फैसला लेते हुए फरार बाबू संजीव सिंह और निलंबित प्रधान सहायक तनुज श्रीवास्तव के रिक्त पटलों पर वरिष्ठ लिपिक स्वदेश श्रीवास्तव और एक अन्य सहायक लिपिक की तैनाती कर दी। यह बदलाव केवल पटलों का हस्तांतरण नहीं, बल्कि उस वसूली सिंडिकेट के ताबूत में आखिरी कील माना जा रहा है, जिसे शालिनी श्रीवास्तव ने संरक्षण दे रखा था।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन

गोरखपुर ।

गोला ब्लॉक के नगर पंचायत कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, उनके कार्यों की सराहना करना तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लालती देवी(चेयर मैन) उपस्थित रहीं। उनके साथ सभासद श्री शत्रुघ्न सावधान (जिला कोषाध्यक्ष), श्री लल्लन प्रसाद (जलकर लिपिक) तथा श्री अमरनाथ जायसवाल (कंप्यूटर ऑपरेटर) भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर डिजिटल सखी परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री ध्रुवचंद वर्मा जी तथा क्लस्टर कॉर्डिनेटर अजीत शेखर जी के नेतृत्व में गोला ब्लॉक की सभी डिजिटल सखियों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वर्ष 2023 से अब तक उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों को आमंत्रित किया गया और उनके सराहनीय कार्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि श्रीमती लालती देवी ने अपने संबोधन में डिजिटल सखी परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि यह परियोजना ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा सरकारी योजनाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि महिलाएँ आगे बढ़ेंगी तो समाज और देश दोनों का विकास तेजी से होगा। इस अवसर पर प्रोजेक्ट मैनेजर श्री ध्रुवचंद वर्मा जी ने BAIF संस्था एवं डिजिटल सखी परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह परियोजना ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल सेवाओं से जोड़कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम के अंत में वर्ष 2023 से अब तक उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया तथा उन्हें पुरस्कार देकर उनके प्रयासों की सराहना की गई। इससे महिलाओं में उत्साह और आत्मविश्वास का संचार हुआ तथा अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। अंततः सभी अतिथियों, डिजिटल सखियों एवं उपस्थित महिलाओं के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

समाजसेविका स्वर्णिमा जायसवाल बनायी गयीं ब्राण्ड एम्बेसडर

जौनपुर।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत समाजसेविका स्वर्णिमा जायसवाल को जौनपुर का ब्राण्ड एम्बेसडर बनाया गया। यह मनोनयन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया जिसकी जानकारी होने पर श्रीमती जायसवाल के परिवार में जहां खुशी की लहर दौड़ गयी, वहीं उनके शुभचिन्तकों ने बधाई दिया। नगर के ख्वाजगी टोला स्थित उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। नगर के तमाम समाजसेवियों सहित शुभचिन्तकों ने श्रीमती जायसवाल को बधाई देते हुये सरकार द्वारा समाज हित में लिये गये इस निर्णय की सराहना किया। साथ ही कहा कि स्वर्णिमा जी के नेतृत्व में मिशन का अभियान कामयाब होगा।

एलपीजी सिलेंडर को लेकर सियासत तेज, पीएम ने कहा- अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखो, जमाखोरी करने वाले जाएंगे जेल

नई दिल्ली। देश में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर उठीं आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी तरह के दुष्प्रचार और घबराहट फैलाने की कोशिशों का आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाए। मोदी सरकार ने साफ किया है कि देश में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है और किसी भी संकट से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां पहले से मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि कुछ लोग एलपीजी आपूर्ति की स्थिति को लेकर अनावश्यक घबराहट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिया कि ऐसी हर कोशिश पर कड़ी नजर रखी जाए और तथ्यों के साथ उसका तुरंत जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया सहित हर मंच पर विपक्ष के दुष्प्रचार का आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का कहना था कि मौजूदा स्थिति किसी एक देश तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण दुनिया के कई देशों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भारत की तैयारियां मजबूत हैं और सरकार किसी भी तरह की आपूर्ति बाधा से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। सरकार का जोर इस बात पर है कि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की उपलब्धता में किसी प्रकार की समस्या न होने दी जाए। इसी बीच, केंद्र सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी सख्त कदम उठाए हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों के साथ विस्तृत बैठक कर देशभर में एलपीजी की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। लगभग दो घंटे चली इस बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में राज्यों को निर्देश दिया गया कि एलपीजी से जुड़ी पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसमें बोटलिंग प्लांट, वितरण नेटवर्क और परिवहन व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर रोजाना एलपीजी की उपलब्धता की समीक्षा करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कालाबाजारी की कोशिशों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करें। सूत्रों के अनुसार रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को भी एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने होटल और रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को दी जाने वाली एलपीजी आपूर्ति पर कुछ नियंत्रण लगाए हैं, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त गैस उपलब्ध रह सके। हालांकि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाओं पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने चौबीस घंटे संचालित होने वाले अपने नियंत्रण कक्ष को और मजबूत किया है।

ईरान में तनाव के बीच होर्मुज पार कर मुंबई पहुंचा तेल टैंकर

भारत-ईरान के विदेश मंत्रियों ने तीन बार बातचीत की

भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच पिछले कुछ दिनों में तीन बार बातचीत हुई है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी। उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री अपने ईरानी विदेशमंत्री के साथ लगातार संपर्क में हैं। जायसवाल ने कहा कि युद्ध का असर हर जगह दिखाई दे रहा है और इससे कई देशों के लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संघर्ष का असर केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कई देशों और लोगों पर पड़ रहा है।

भारत के लिए खुला है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज - हरदीप पुरी

राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत लंबे समय तक संकट का सामना कर सकता है. एलपीजी का उत्पादन 28 फीसदी बढ़ा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता भारत के लिए खुला है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 20 फीसदी आपूर्ति प्रभावित है. देश में अभी पर्याप्त गैस है. गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है. सोएनजी की 100 फीसदी सप्लाई हो रही है. राहुल गांधी के सवाल पर जवाब देते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा, हमारे पास पर्याप्त गैस और तेल है. भारत कई देशों से क्रूड ऑयल खरीद रहा है. होर्मुज संकट से तेल की आपूर्ति पर असर हुआ है. भारत के पास पर्याप्त कच्चा तेल मौजूद है.

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक लाइबेरियाई ध्वज वाला कच्चे तेल का टैंकर, जिसकी कमान एक भारतीय कप्तान के हाथ में थी, रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर सुरक्षित रूप से मुंबई बंदरगाह पहुंच गया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार यह टैंकर सऊदी अरब के रास तनुरा बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर आया था।

मैरिटाइम ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, इस टैंकर ने 1 मार्च को सऊदी अरब के रास तनुरा पोर्ट से कच्चा तेल लोड किया था और 3 मार्च को वहां से रवाना हुआ। 8 मार्च को जहाज को होर्मुज जलडमरूमध्य में ट्रैक किया गया, जिसके बाद यह कुछ समय के लिए ट्रैकिंग सिस्टम से गायब हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज ने जोखिम भरे समुद्री क्षेत्र से गुजरते समय अपना ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रांसपोंडर बंद कर दिया था। यह प्रणाली जहाज की पहचान, स्थिति, गति और दिशा की जानकारी प्रसारित करती है, जिससे समुद्री यातायात को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।

जहाज में कितना तेल है मौजूद?

टैंकर बुधवार दोपहर करीब 1 बजे मुंबई पोर्ट पहुंचा और शाम 6:06 बजे जवाहर द्वीप टर्मिनल पर बर्थ किया गया। जहाज में लगभग 1,35,335 मीट्रिक टन सऊदी कच्चा तेल है, जिसे पूर्वी मुंबई के माहुल स्थित रिफाइनरियों को आपूर्ति किया जाएगा। तेल उतारने की प्रक्रिया करीब 36 घंटे तक चलने की संभावना है। टैंकर पर कुल 29 चालक दल के सदस्य हैं, जिनमें भारतीय, पाकिस्तानी और फिलीपीनी नागरिक शामिल हैं।

ईरान की अनुमति के बाद जलडमरूमध्य से गुजरा टैंकर

अधिकारियों के अनुसार टैंकर ने सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरूमध्य को पार किया, जो फारस की खाड़ी को वैश्विक बाजारों से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। हाल के सैन्य घटनाक्रमों के बाद इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पर सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं, ऐसे में टैंकर का सुरक्षित गुजरना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ईरान जंग के बीच भारत को सफल सप्लाई

हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 150 मिसाइलें दागीं

24 घंटे में 179 लोग घायल; रिपोर्ट- अमेरिका पर भी ईरानी हमले का खतरा

तेल अवीव/तेहरान।

अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 13वां दिन है। इजराइल को ईरान के साथ-साथ पड़ोसी देश लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बुधवार को ईरान समर्थक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 150 मिसाइलें दागीं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर रॉकेट और मिसाइलों रोक दिया, लेकिन कुछ जगहों पर मलबा गिरने से आग लग गई। इसी बीच इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अलग-अलग हमलों में देश भर में पिछले 24 घंटे में 179 लोग घायल हुए हैं। जबकि जंग शुरू होने के बाद से अब तक कुल 2,745 लोग घायल हो चुके हैं। उधर अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने कैलिफोर्निया के पुलिस विभाग को चेतावनी दी है कि ईरान, अमेरिका के पश्चिमी तट पर जवाबी हमला कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी गई।

यूएन में भारत समेत 135 देशों ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में छठे (गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल) के प्रस्ताव का भी समर्थन किया है। इस प्रस्ताव के साथ अब तक 135 देश जुड़ चुके हैं।

यह प्रस्ताव खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और हमलों को लेकर लाया गया है। इसका मुख्य मकसद इलाके में हालात को और बिगड़ने से रोकना, जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित रखना और ऊर्जा सप्लाई को बाधित होने से बचाना है।

फारूक अब्दुल्ला बोले- ऊपर वाले ने बचाया

हमलावर ने सिर पर कुछ इंच दूर से गोली चलाई थी, सुरक्षाकर्मी की वजह से बचे

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार रात एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। हमलावर ने सिर पर कुछ इंच दूर से गोली चलाई थी। गनीमत रही कि सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर का हाथ ऊपर कर दिया और उन्हें गोली नहीं लगी। अधिकारियों के मुताबिक फारूक जम्मू में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। उनके साथ राय के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी थे। फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा- मुझे ऊपर वाले ने बचाया है। शादी से निकलते समय मैंने कुछ आवाज सुनी, मुझे लगा कि यह पटाखा है। बाद में मुझे बताया गया कि एक आदमी ने पिस्तौल से दो गोलियां चलाईं। सुरक्षाकर्मियों ने बीच-बचाव किया, जिससे हथियार ऊपर की ओर हो गया और नुकसान होने से बच गया। वहीं, हमलावर कमल ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। हमलावर को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में फायरिंग की घटना के बाद फारूक अब्दुल्ला से फोन पर बात की और उनका हालचाल पूछा। फारूक अब्दुल्ला की हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी कमल सिंह जामवाल को जम्मू पुलिस मेडिकल जांच के लिए ले गई। पुलिस के साथ ले जाते समय जामवाल ने कहा- मैंने किसी के कहने पर गोली नहीं चलाई। मैंने अपनी मर्जी से गोली चलाई है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि 70 साल के हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से आकर फारूक के सिर पर रिवॉल्वर तान दी। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हमलावर का हाथ हटाया जिससे फायर हवा में हो गया।

इथियोपिया में लैंडस्लाइड से 50 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लापता

नई दिल्ली। इथियोपिया में हुए जानलेवा लैंडस्लाइड में 50 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। समाचार एजेंसी एपी ने एक अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी। यह समाचार प्रारंभिक सूचना और उपलब्ध आधिकारिक/ रिपोर्ट्स के आधार पर प्रकाशित किया गया है। मामले से जुड़ी जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। जैसे-जैसे अधिकृत पुष्टि और विस्तृत विवरण प्राप्त होंगे, खबर को अपडेट किया जाता रहेगा। पाठकों से अनुरोध है कि ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।

संसद के बाहर नारेबाजी- नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब

नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को विपक्ष के सांसदों ने देश में सिलेंडर संकट के मुद्दे पर हंगामा किया। सांसदों ने संसद के बाहर नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब के नारे लगाए। राहुल गांधी ने सरकार से एलपीजी की कमी से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता किया, इसलिए बड़ी समस्या आने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी के नोटिस के बाद संसद गैस संकट पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। इससे पहले लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला 10 फरवरी के बाद अध्यक्ष की चेयर पर बैठे। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव बुधवार को खारिज हो गया। राहुल गांधी ने कहा- प्रधानमंत्री कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वह खुद घबराए हुए लग रहे हैं, बिल्कुल अलग वजहों से। वे एप्स्टीन-अदाणी केस की वजह से पैनिक है। आपने कल देखा कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली थी। वह देश से कह रहे हैं कि घबराएं नहीं, जबकि वह खुद परेशान लग रहे हैं। उधर, राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर हमले का मुद्दा उठाया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा- एलपीजी की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। सवाल यह उठता है कि सरकार इतने समय तक इनकार क्यों करती रही? सरकार क्यों कहती रही कि 'सब कुछ ठीक है', सच्चाई पर्याप्त है और सब कुछ नियंत्रण में है? सरकार ने पहले से एलपीजी का स्टॉक क्यों नहीं किया या सप्लाई के दूसरे स्रोत क्यों नहीं तलाशे?

नागरिकों को क्यों परेशानी झेलनी पड़ रही है और सरकार उनकी चिंताओं को क्यों नहीं सुन रही? हर बार राष्ट्रीय संकट आने पर प्रधानमंत्री कहां चले जाते हैं? वे चुनावी रैलियों में जाते हैं और विपक्ष पर हमला करते हैं, लेकिन संसद में आकर सवालों का जवाब नहीं देते।

प्रधानमंत्री ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के साथ समझौता किया है - राहुल गांधी

नई दिल्ली। । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऊर्जा सुरक्षा मामले में केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने संकट से निपटने के लिए अग्रिम तैयारी किए जाने का आह्वान करते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं किया गया, तो भविष्य में करोड़ों लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। राहुल का ये बयान एलपीजी की कमी को लेकर आई खबरों मीडिया रिपोर्ट्स के बीच आया है। उन्होंने संसद परिसर में पत्रकारों से बात करने के अलावा सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए भी सरकार को घेरा।

संसद में पीएम मोदी के नहीं आने पर तीखा हमला

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की संसद में अनुपस्थिति को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने अपने फेसबुक पर संसद परिसर में विरोध-प्रदर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, संसद से नरेंदर गायब, देश से सिलेंडर गायब! इस मामले में फेसबुक पोस्ट के अलावा राहुल ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं क्योंकि वह फंसे हुए हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के लोग सुरक्षित रहें और देश की ऊर्जा सुरक्षा का प्रबंधन हम स्वयं करें।

हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जोर देकर कहा, गैस और ईंधन एक बड़ी समस्या बनने वाले हैं क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि यह ईरान के होर्मुज क्षेत्र से तेल के जहाजों को आने की अनुमति देने या न देने से भी बड़ा मुद्दा है। बकौल राहुल गांधी, पश्चिम एशिया में हो रहा युद्ध मूल रूप से वर्तमान विश्व व्यवस्था के बारे में है। अस्थिर समय को देखते हुए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि संभावनाओं पर गहराई से विचार करे, जिससे देश के लोगों को नुकसान न उठाना पड़े।

राजनीतिक बयान नहीं दे रहे

ऊर्जा सुरक्षा पर चिंता और इस मुद्दे पर सियासत के आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने कहा, वह कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहे हैं। यदि समस्या ईरान के स्तर पर भी हल हो जाए, तब भी यह संकट दूर नहीं होगा। दुनिया की संरचना बदल रही है। पीएम मोदी को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत के लोग सुरक्षित रहें। उम्मीद है कि सरकार विपक्ष की बात सुनेगी।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिले अखिलेश, बोले- नकली संतों का अंत होने जा रहा है

लखनऊ ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को लखनऊ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम यहां पर आशीर्वाद लेने के लिए आए थे क्योंकि असली संतों से मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि भाजपा के लोग हर अच्छी बात का विरोध करते हैं। जब हमारी सरकार थी तो हमने डेयरी बनवाई थी जिससे गरीबों का लाभ हो और गायों की भी देखभाल हो लेकिन भाजपा के लोग हर अच्छी बात का विरोध करते हैं। सपा की सरकार में पहला काफ मिल्क प्लांट लगाया गया था जिसे भाजपा की सरकार ने बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि हम पहले भी गाय की भलाई के लिए काम कर रहे थे आगे भी फैसले करेंगे। अखिलेश यादव ने प्रदेश के डिप्टी सीएम को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि भाजपा की बैठक से दोनों डिप्टी सीएम को डांटकर बाहर कर दिया गया।

बताया गया कि वहां पर टिकट को लेकर चर्चा होने वाली थी पर ये लोग तो शायद जहां से लड़े वहां जीते ही ना। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत सरकार के गलत फैसले के कारण लोगों को एलपीजी संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को घरों में चूल्हे और भट्ठे जलाना पड़ रहा है। हालत ये है कि मुख्यमंत्री के अपने जनपद में एलपीजी को लेकर मारामारी हो रही है। लोग गैस के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों में योगी मुख्यमंत्री जी का प्रभाव आ गया है यही कारण है कि वो लखनऊ में भी नहीं लग पा रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं।

मां ने चार बेटियों को कुएं में फेंककर मार डाला, फिर खुद लगाई फांसी

सागर । मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। जिले के केसली थाना क्षेत्र के खमरिया गांव में एक मां ने अपनी ही चार मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। महिला ने चारों बच्चियों को कुएं में फेंक दिया और उसके बाद खुद पेड़ पर जाकर फांसी के फंदे पर झूल गई। इस सामूहिक मौत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में मातम पसर गया है। मिली जानकारी के अनुसार, मृतिका की पहचान 30 वर्षीय सविता लोधी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सविता ने गुरुवार को अपनी चारों बेटियों को घर के पास स्थित हरपाल घोसी के खेत में बने कुएं में धकेल दिया। पानी गहरा होने के कारण चारों मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में सबसे बड़ी बेटी की उम्र महज 7 साल बताई जा रही है। अपनी बेटियों की मौत के घाट उतारने के बाद सविता ने आत्महत्ती कदम उठाते हुए खुद को भी फांसी लगा ली। घटना की सूचना मिलते ही केसली थाना पुलिस और टड़ा चौकी की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुएं से चारों बच्चियों के शव बाहर निकाले। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को भी बुलाया गया है, जो मौके से साक्ष्य जुटा रही है। सभी पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मृतिका के पति और ससुराल पक्ष से पूछताछ कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि महिला पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी। अंदेशा जताया जा रहा है कि घरेलू विवाद या किसी गहरे तनाव के चलते महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया है। हालांकि, पुलिस अभी किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचने से बच रही है। सागर जिले के इस छोटे से गांव में आज हर आंख नम है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है।

कृषि-खाद्य क्षेत्र में महिलाओं को नीति-निर्माण व निर्णय प्रक्रिया में अधिक भूमिका मिले- राष्ट्रपति

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कहा कि कृषि एवं कृषि-खाद्य क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को नीति निर्माण, निर्णय-प्रक्रिया और नेतृत्व पदों पर अधिक भूमिका मिलनी चाहिए। उन्होंने इस क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला में लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने तीन दिवसीय महिलाएं एवं कृषि-खाद्य प्रणाली वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सफलता की कहानियों को व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए, ताकि समाज उनके योगदान के बारे में अधिक जान पाए।

मुर्मू ने भारत द्वारा अपनाए गए महिला-नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हर स्तर पर भागीदारी बढ़ाने से समावेशी कृषि वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति ने महिला किसानों को भूमि स्वामित्व, तकनीकी ज्ञान और संस्थागत वित्त तक पहुंच के लिए लक्षित सहायता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। तकनीक की भूमिका पर उन्होंने कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित पहल सरलाबेन का उल्लेख किया, जो सरकार के पशुधन देखभाल दृष्टिकोण से प्रेरित है और महिला किसानों के लिए नई संभावनाएं खोल रही है। सरकार के तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार की महिला किसानों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का जिक्र करते हुए मुर्मू ने कहा कि अगली पीढ़ी को कृषि क्षेत्र में सार्थक योगदान देने के लिए इन अग्रणी महिलाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 को महिला किसान अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किए जाने का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की नेतृत्व भूमिका बढ़ाने और लैंगिक अंतर को कम करने का वैश्विक आह्वान है। उन्होंने बताया कि पिछले दशक में केंद्र सरकार की कई योजनाओं ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 57 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें 56 प्रतिशत महिलाओं के हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 68 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार और 90 लाख स्वयं सहायता समूह जोड़े गए हैं। इस मिशन के तहत 4.6 करोड़ से अधिक महिला किसानों को बेहतर कृषि पद्धतियां अपनाने में सहायता मिली है। उन्होंने नमो ड्रोन दीदी योजना का भी उल्लेख किया जिसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि सटीक कृषि तकनीकों का उपयोग बढ़ सके। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से तीन करोड़ से अधिक महिलाएं पहले ही सालाना एक लाख रुपये से अधिक आय प्राप्त कर रही हैं। वहीं 2025-26 के केंद्रीय बजट में हर जिले में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए शी मार्ट (स्वयं सहायता उद्यमी बाजार) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है जिससे महिलाओं को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा।

अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने लोगो, पृथ्वी, समृद्धि, शांति और साझेदारी के वैश्विक ढांचे का उल्लेख करते हुए सभी पक्षों से विचार एवं कार्य दोनों में लैंगिक समानता को विशेष प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

मुर्मू ने कहा, यदि कृषि सहित हर क्षेत्र में प्रभावी लैंगिक समावेशन सुनिश्चित किया जाए तो हम न केवल सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करेंगे, बल्कि पृथ्वी को अधिक संवेदनशील और सामंजस्यपूर्ण भी बना सकेंगे। कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान, एम एल जाट, आर एस परोदा और त्रिलोचन महापात्र सहित कई विशेषज्ञ और अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह तीन दिवसीय सम्मेलन महिलाओं की सफलता की कहानियों को साझा करने, कृषि नीतियों में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करने, तथा उद्यमिता, वित्तीय मॉडल और बाजार संपर्क जैसे विषयों पर चर्चा पर केंद्रित है।